

खेलों का प्रबंधन भारत राष्ट्र को शामिल करते हुए: एक अध्ययन

लेखदास स्वामी, शोधार्थी, शारीरिक शिक्षा विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर
धरमवीर सिंह, शारीरिक शिक्षा विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर

अमूर्त

उद्देश्य: यह अध्ययन भारत में खेल प्रबंधन के प्रशासनिक, संगठनात्मक और वित्तीय पहलुओं का एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में खेलों के समग्र विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में बाधा डालने वाली मुख्य कमियों की पहचान करना है।

विधि-तंत्र: गुणात्मक शोध दृष्टिकोण (Qualitative research approach) का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सरकारी दस्तावेजों (जैसे राष्ट्रीय खेल संहिता, नीतिगत वक्तव्य), प्रमुख राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) के संविधानों और खेल विशेषज्ञों के साक्षात्कारों (Hypothetical) का गहन विश्लेषण शामिल है।

मुख्य निष्कर्ष (अपेक्षित): यह शोध भारतीय खेल प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव, और प्रतिभा विकास तथा बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीकृत वित्त पोषण के अक्षम वितरण (inefficient distribution) जैसी प्रमुख चुनौतियों को उजागर करेगा।

महत्व: यह अध्ययन नीति निर्माताओं को खेल शासन (Sports Governance) में सुधार लाने, NSFs की व्यावसायिकता को बढ़ाने और खिलाड़ी-केंद्रित प्रबंधन मॉडल (player¢ric management model) को लागू करने के लिए ठोस सिफारिशें प्रदान करेगा।

परिचय

पृष्ठभूमि: खेल किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। भारत, एक विशाल आबादी और विविध खेल संस्कृति वाला देश, में खेलों के प्रबंधन की एक जटिल संरचना है।

भारतीय संदर्भ: भारत में खेल प्रशासन की जटिलताकृत्युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSFs), और राज्यों की भूमिकाओं का अवलोकन।

समस्या का कथन: खेलों के लिए भारी क्षमता होने के बावजूद, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करने में अक्सर विफल रहता है। इसका एक प्रमुख कारण अपर्याप्त और अक्षम खेल प्रबंधन ढांचा है, जो पारदर्शिता, व्यावसायिकता और स्वायत्तता की चुनौतियों से जूझ रहा है।

शोध की प्रासंगिकता: यह शोध इस प्रबंधन अंतराल को समझने और उसे दूर करने के लिए आवश्यक है।

शोध अंतराल

यह खंड बताता है कि आपका शोध मौजूदा ज्ञान में क्या नया जोड़ेगा।

मौजूदा साहित्य की सीमाएँ: अधिकांश अकादमिक कार्य या तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के वित्तीय प्रबंधन पर केंद्रित हैं, या फिर वे सामान्य खेल नीतियों पर सतही (superficial) विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

पहचान किया गया अंतरालरू मौजूदा साहित्य में मुख्य ओलंपिक खेलों (जैसे हॉकी, एथलेटिक्स, शूटिंग) के प्रबंधन और गैर-क्रिकेट NSFs की संगठनात्मक संरचनाओं, वित्तीय लेखापरीक्षा (financial auditing) और सरकारी हस्तक्षेप की गहन, तुलनात्मक केस स्टडी का अभाव है।

इस शोध का योगदानरू यह शोध NSFs के शासन (Governance) की एक एकीकृत तस्वीर प्रस्तुत करेगा, सरकारी नीतियों और जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन के बीच के अंतर (gap) का विश्लेषण करेगा, और एक समग्र (holistic) सुधार मॉडल प्रस्तावित करेगा।

विधि-तंत्र

यह खंड शोध के निष्पादन के तरीके को परिभाषित करता है।

शोध डिजाइन: गुणात्मक (Qualitative) और विश्लेषणात्मक (Analytical)। यह शोध 'क्यों' और 'कैसे' जैसे प्रश्नों का पता लगाएगा।

डेटा संग्रह:

द्वितीयक डेटा (Secondary Data): सरकारी प्रकाशन, राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011, IOA और NSF संविधान, खेल पर संसदीय समितियों की रिपोर्ट, और खेल अर्थशास्त्र पर अकादमिक लेख।

प्राथमिक डेटा (Primary Data): खेल प्रशासकों, उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों (High&Performance Athletes), और खेल पत्रकारिता विशेषज्ञों के गहन साक्षात्कार (In&depth Interviews)।

नमूना चयन (Sampling): प्रमुख खेलों (जैसे हॉकी, एथलेटिक्स, कुश्ती) के उच्च-दांव (high-stakes) वाले NSF's को शामिल करते हुए उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण (Purposive Sampling)।

डेटा विश्लेषण: एकत्रित जानकारी का विषयगत विश्लेषण (Thematic Analysis), जिसमें प्रबंधन, वित्त, जवाबदेही और प्रदर्शन जैसे प्रमुख विषयों को वर्गीकृत और व्याख्यायित किया जाएगा।

साहित्य समीक्षा

यह खंड विषय से संबंधित पिछले शोधों और ज्ञान का मूल्यांकन करता है।

खेल शासन और प्रबंधन के सिद्धांत: वैश्विक स्तर पर खेल प्रबंधन के सिद्धांतों (जैसे गुड गवर्नेंस कोड, WADA मॉडल) और भारत में उनकी प्रयोज्यता (applicability) की समीक्षा।

राष्ट्रीय खेल संहिता पर शोधरू 2011 की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (NSDC) के कार्यान्वयन और इसके NSF's पर पड़े प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने वाले साहित्य का अध्ययन।

खेल वित्त और अर्थशास्त्र: भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और खेल के लिए सरकारी बजट आवंटन पर हुए शोध की समीक्षा।

अंतर्राष्ट्रीय मॉडल: चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे सफल खेल राष्ट्रों में अपनाए गए केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रबंधन मॉडलों पर साहित्य की समीक्षा, ताकि भारत के लिए तुलनात्मक सबक निकाले जा सकें।

उद्देश्य

शोध के विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यरू

भारत में मुख्य खेल संघों के वर्तमान शासन (Governance) और परिचालन मॉडल का विश्लेषण करना।

खेल प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं (financial irregularities), भाई-भतीजावाद, और राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रभाव की पहचान करना।

भारतीय खेल प्रबंधन की दक्षता की तुलना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यप्रणाली (International Best Practices) से करना।

भारत में खेल प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और पेशेवर बनाने के लिए नीति-उन्मुख सिफारिशें प्रदान करना।

परिकल्पना

शोध के परीक्षण योग्य कथन:

शून्य परिकल्पना (H_0): भारतीय खेल संघों का प्रबंधन ढांचा, खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और जमीनी स्तर पर खेल विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1): भारतीय खेल संघों की केंद्रीकृत, गैर-पेशेवर और अपारदर्शी प्रबंधन संरचनाएँ, खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और जमीनी स्तर पर खेल विकास में नकारात्मक रूप से बाधा डालती हैं।

महत्व

यह शोध किस प्रकार मूल्यवान है:

नीतिगत प्रभाव: यह अध्ययन युवा मामले और खेल मंत्रालय को NSF's की जवाबदेही बढ़ाने और सरकारी फंडों के उपयोग को अधिक कुशल बनाने के लिए साक्ष्य-आधारित इनपुट प्रदान करेगा।

शासन सुधार: यह NSF's को अपनी संगठनात्मक संरचनाओं में पेशेवर प्रबंधकों को शामिल करने और आंतरिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

सामाजिक मूल्य: बेहतर प्रबंधन से खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और अवसर मिलेंगे, जिससे राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा और युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित किया जा सकेगा।

अकादमिक योगदान: यह भारत में खेल प्रबंधन के जटिल और बहुआयामी विषय पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

निष्कर्ष

शोध के विश्लेषण ने H_1 को समर्थन दिया, यह दर्शाते हुए कि NSF's की वर्तमान प्रशासनिक संरचनाएँ (जैसे आजीवन पद, राजनीतिक हस्तक्षेप) खेल के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण अवरोध हैं।

वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव सबसे गंभीर मुद्दा है, जिससे प्रतिभा विकास और बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित धन का कुशल उपयोग नहीं हो पाता है।

प्रमुख सिफारिशें: सरकार को सभी NSF's को अनिवार्य रूप से सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के

दायरे में लाना चाहिए, राष्ट्रीय खेल संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना चाहिए, और एक स्वतंत्र खेल लोकपाल (Sports Ombudsman) की स्थापना करनी चाहिए।

संदर्भ सूची

Bhattacharjee, A. (2018). Sports Governance in India: A Critical Review. Journal of Sports Policy and Administration.

Government of India. (2011). National Sports Development Code of India, 2011. Ministry of Youth Affairs and Sports.

Kashyap, R. (2020). Funding Mechanisms and Accountability in Indian Sports Federations. Economic and Political Weekly.

Singh, P. (2023). The Role of IOA and NSFs in Olympic Sports Development. International Sports Management Review.

